कामये दुरवतप्राणाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

जागृति

वर्ष: 64 | अंक: 09 | मुम्बई | अगस्त 2020

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 24 जुलाई, 2020 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग की कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत प्रशिक्षित 100 कारीगरों को 100 विद्युत चालित कुम्हारी चाकों का वितरण किया।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका
खादी और ग्रामोद्योग आयोग

वर्ष 64 अंक 09 मुंबई अगस्त 2020

जागृति

कामये दुरवतमानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

संपादक मंडल

अध्यक्ष

श्रीमती प्रीता वर्मा

संपादक
एम. राजन बाबू

उप संपादक
सुबोध कुमार

अवर उप संपादक
शिव दयाल कुशवाहा

वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक
सरस्वती खनका

वरिष्ठ कलाकार
संजय एस. सोमदे

कलाकार
चंद्रशेखर पुलवटकर,
दिलीप पालकर

के. सुब्बाराव, द्वारा प्रचार, फिल्म एवं
लोक शिक्षण कार्यक्रम निदेशालय
खादी और ग्रामोद्योग आयोग
ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम)
मुम्बई - 400 056 के लिए प्रकाशित
टेलिफैक्स: 022-26719465
ई-मेल: editorialpublicitykvic@gmail.com
वेबसाईट: www.kvic.org.in

प्रचार, फिल्म एवं लोक शिक्षण कार्यक्रम निदेशालय
खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड
विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई - 400 056 में प्रकाशित

आवश्यक नहीं कि पत्रिका में प्रकाशित लेखों तथा व्यक्त विचारों से खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा सम्पादक सहमत हों।

इस अंक में...

समाचार सार .....3 to 17

- समावेशी विकास की दिशा में कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाना एक बड़ा कदम .....
- अर्धसैनिक बल अब खादी सरसों तेल का स्वाद चखेंगे .....
- चर्म कारीगरों के लिए केवीआईसी ने खोला दिल्ली में अत्याधुनिक फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र .....
- "स्थानीय से वैश्विक" विषय पर भविष्य के राजनयिकों के साथ अध्यक्ष,केवीआईसी की चर्चा .....
- केवीआईसी ने दौसा में प्रशिक्षित कारीगरों को 100 विद्युत चालित कुम्हारी चाक़ों का वितरण किया .....
- केवीआईसी हुआ सख़्त; प्रधान मंत्री की फोटो इस्तेमाल कर नकली खादी मास्क बेचने वाले के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज .....
- खादी ग्रामोद्योग आयोग को रेड क्रॉस सोसाइटी से मिला 1.80 लाख फेस मास्क खरीद का ऑर्डर .....
- नीति आयोग के सीईओ ने किया गांधी आश्रम सेवापुरी का दौरा...
- आत्मनिर्भर भारत के लिए केवीआईसी की चंदन और बांस के वृक्षारोपण के पहल की सराहना .....
- बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र, पंजोखरा में विद्युत चालित चाक वितरित
- गांधी आश्रम में समीक्षा बैठक.....

लेख.....18-21

- कोरोना संकट और स्व-रोज़गार के अवसर

सोशल मीडिया व प्रेस कवरेज.....22-25

गृह मंत्री द्वारा 100 विद्युत चालित कुम्हारी चाक़ों का वितरण

समावेशी विकास की दिशा में कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाना एक बड़ा कदम

श्री अमित शाह

आर्थिक हाशिये पर जीवन व्यतीत कर रहे भारत के कुम्हार समुदाय को "आत्मनिर्भर" बनने की दिशा के साथ उन्हें सशक्त बनाने पर बल देते हुए , माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 24 जुलाई, 2020 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग की कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत 100 प्रशिक्षित कारीगरों को 100 विद्युत चालित कुम्हारी चाक का वितरण किया।

श्री अमित शाह ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गांधीनगर के अपने संसदीय क्षेत्र में कलोल तालुका के तहत बलवा गाँव में इन विद्युत चालित कुम्हारी चाकों का वितरण किया।

कुम्हार सशक्तिकरण योजना के बारे में बताते हुए, गृह मंत्री ने कहा कि मिट्टी के बर्तनों की पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करते हुए आर्थिक हाशिये पर रहने वाले कुम्हार समुदाय को मजबूत बनाने की दिशा में पहल की जाएगी ।

उन्होंने पांच कुम्हारों - अशोक भाई प्रजापति, राजेश भाई प्रजापति, जयंती भाई प्रजापति, सुरेखाबेन प्रजापति और वेलजी भाई प्रजापति के साथ भी बातचीत की - जिन्हें मिट्टी के बर्तनों में केवीआईसी द्वारा 10-दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें विद्युत चालित कुम्हारी चाक और अन्य उपकरण प्रदान किए गए।

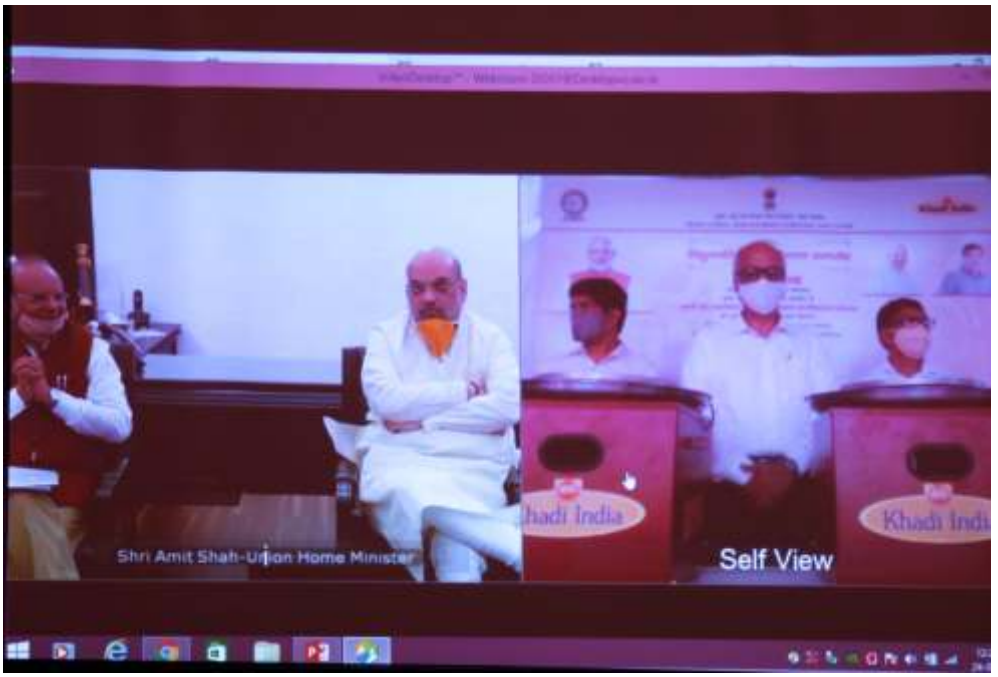

श्री अमित शाह ने कहा, "मैं अपने कुम्हारों के जीवन में आए बदलाव को देखकर खुश हूँ। केंद्र में हमारी सरकार प्रजापति समुदाय की बेहतर आजीविका के लिए हमेशा चिंतित है। इलेक्ट्रिक चाक का वितरण हमारे प्रधानमंत्री से गुजरात के लोगों के लिए एक उपहार है।

"गृह मंत्री ने कुम्हारों को आश्वासन दिया कि रेलवे के साथ टाई-अप सहित व्यवस्था उनके उत्पादों को बेचने के लिए उचित विपणन चैनल प्रदान करने के लिए बनाई जाएगी।"

श्री अमित शाह ने अपनी योजनाओं के माध्यम से कमजोर वर्गों को स्थायी रोजगार के अवसर प्रदान करने में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के प्रयासों की सराहना की। कुम्हार सशक्तिकरण योजना कुम्हारों के समुदाय को "आत्मनिर्भर" बनाने की दिशा में एक ऐसा ही कदम है। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि केवीआईसी समाज के वंचित और निचले के वर्गों के लाभ के लिए काम करना जारी रखेगा।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने बताया कि देश भर में अब तक 17,000 से अधिक विद्युत चालित कुम्हारी चाक वितरित किए जा चुके हैं, जिससे कुम्हार समुदाय के लगभग 70,000 लोग लाभान्वित हुए हैं। "इसने कुम्हारों के जीवन को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। विद्युत चालित कुम्हारी चाकों के साथ, मिट्टी की वस्तुओं का उत्पादन कई गुना बढ़ गया है।

वर्तमान में, देश भर में हर दिन लगभग 2 करोड़ कुल्हड़ बनाए जाते हैं। कुम्हार इन कुल्हड़ को 400 रेलवे स्टेशनों पर सफलतापूर्वक बेच रहे हैं जो उनके लिए एक आदर्श विपणन मंच है। बता दें कि गुजरात के कई क्षेत्र, विशेष रूप से कच्छ और सौराष्ट्र, पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों की कला के लिए प्रसिद्ध हैं। 2018 में कुम्हार सशक्तिकरण योजना के शुभारंभ के बाद से, केवीआईसी ने गुजरात के विभिन्न गांवों से लगभग 750 कुम्हारों को प्रशिक्षित किया है।

मिट्टी के बर्तनों के निर्माण में उन्हें प्रशिक्षण देने के

अलावा, केवीआईसी ने उन्हें मिट्टी के मिश्रण के लिए विद्युत चालित कुम्हारी चाक और ब्लॉंजर मशीन जैसे अन्य उपकरण भी वितरित किए हैं। इसने मिट्टी के बर्तनों के निर्माण की प्रक्रिया से कुम्हार कारीगरों के कठिन श्रम को खत्म कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप कुम्हारों के उत्पादन और उच्च आय में 3-4 गुना वृद्धि हुई है।

गांधीनगर जिले में, केवीआईसी ने 100 कुम्हारों को प्रशिक्षित किया है और 100 विद्युत चालित कुम्हारी चाक और 10 ब्लॉंजर मशीनें वितरित की हैं। कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत कुम्हारों की औसत आय लगभग 3000 रुपये प्रति माह से बढ़कर लगभग 10,000 रुपये प्रति माह हो गई है।

◆◆◆◆

खादी ग्रामोद्योग आयोग और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के बीच समझौता

अर्धसैनिक बल अब खादी सरसों तेल का स्वाद चखेंगे

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के साथ मिलकर सरसों के तेल की आपूर्ति कर भारत को "आत्मनिर्भर" बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। 31 जुलाई 2020 को, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) तथा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) ने इस संदर्भ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष, श्री विनय कुमार सक्सेना की उपस्थिति में श्री वीके नागर, निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग एवं भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के उप महानिरीक्षक (डी आई जी) श्री रमाकांत शर्मा ने हस्ताक्षर किए।

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए "आत्मनिर्भर भारत अभियान" के समर्थन में स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए अर्धसैनिक बलों को माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के निर्देश पर यह विकासात्मक पहल की गई है। इस पहल का माननीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, श्री नितिन गडकरी ने स्वागत किया है।

श्री अमित शाह ने सम्पूर्ण भारत में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कैंटीन के माध्यम से केवल "स्वदेशी" उत्पादों को बेचना अनिवार्य कर दिया है। गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों के लिए प्रावधान में शामिल सभी वस्तुओं की खरीद के लिए भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।

आईटीबीपी जल्द ही उच्च गुणवत्ता वाले 1200 क्विंटल की कच्ची घानी सरसों के तेल की आपूर्ति का आदेश

जारी करेगा, जिसकी आपूर्ति खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत कार्यरत इकाइयों के माध्यम से एक महीने के भीतर की जाएगी।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने उनकी इस पहल के लिए माननीय गृह मंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि एमओयू एक ऐतिहासिक कदम था क्योंकि यह पहली बार है जब खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किसी भी सामग्री की आपूर्ति के लिए अर्धसैनिक बलों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रयास स्थायी स्थानीय रोजगार सृजित करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है । श्री सक्सेना ने कहा, "हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे जवानों को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला तेल उपलब्ध कराना, वह भी समय पर हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।"

केवीआईसी और आईटीबीपी ने एक वर्ष की अवधि के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसे भविष्य में पुनः बढ़ाया जाएगा। कपास मैट (दरी), कंबल, चादरें, तकिये के कवर, अचार, शहद, पापड़ और सौंदर्य प्रसाधन आदि उत्पादों की आपूर्ति भी आगे की जाएगी। तेल और दरी का कुल मूल्य लगभग 18 करोड़ रुपये होगा।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने उल्लेखनीय रूप से, हाल ही में परीक्षण के तौर पर सीएपीएफ कैंटीन को शहद, अचार, खाद्य तेल, अगरबत्ती, पापड़, आंवला कैंडी और सूती तौलिए आदि उत्पादों की आपूर्ति की गई है। इसके अलावा, आपूर्ति की संख्या में 63 नए उत्पादों की एक सूची में जोड़ने के लिए तैयारी की जा रही है।

◆◆◆◆

चर्म कारीगरों के लिए केवीआईसी ने खोला दिल्ली में अत्याधुनिक फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र

सामाजिक हाशिये पर जी रहे समुदाय के "जूता बनाने वाले "चर्म कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने 16 जुलाई, 2020 को दिल्ली में अपनी तरह के पहले फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया।

केंद्र को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की आगरा स्थित एक इकाई, केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान (CFTI) के तकनीकी जानकारों के सहयोग से स्थापित किया गया है। गांधीघाट, राजघाट स्थित "केवीआईसी - सीएफटीआई फुटवियर ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर", उच्च गुणवत्ता के जूते बनाने के लिए चर्म कारीगरों को 2 माह का एक विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करेगा।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री वी.के.

सक्सेना ने केंद्र का उद्घाटन करते हुए चर्म कारीगरों को "चर्म चिकित्सक" (चमड़े के डॉक्टर) के नाम से संबोधित किया। प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा दो माह का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा करने के पश्चात जूता बनाने के व्यवसाय को शुरू करने में भी यह प्रशिक्षण केंद्र उन्हे सहायता प्रदान करेगा। कारीगरों को भविष्य में उनकी गतिविधियों को सम्पन्न करने के लिए 5000 रुपये का टूल किट भी प्रदान किये जायेंगे।

उन्नत टूल किट और मशीनरी से युक्त "केवीआईसी - सीएफटीआई फुटवियर ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर" के उद्घाटन में लॉकडाउन के कारण हालांकि देरी हुई, किंतु इसकी स्थापना दो माह से भी कम समय के रिकॉर्ड समय में की गई है। शुरुआत में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को 40 चर्म कारीगरों के एक बैच के लिए डिज़ाइन किया गया था, किंतु कोरोना महामरी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दूरी के मानदंडों को अपना कर यह संख्या 20 कारीगरों के एक बैच तक सीमित कर दी गई है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग वाराणसी में भी इसी तरह का फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने जा रहा है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि चर्म कारीगरों या 'चर्म चिकित्सक' के प्रशिक्षण को "सबका साथ, सबका विकास" के माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के साथ जोड़ दिया गया है।

"इससे पहले श्री सक्सेना ने कहा कि चीन, वियतनाम और ताइवान जैसे देशों से भारी मात्रा में जूते और चमड़े के अन्य सामान आयात किए गए थे। हालांकि सरकार ने फुटवियर के आयात पर अंकुश लगाने का फैसला किया है और इसलिए फुटवियर के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने का यह एक सुनहरा अवसर है और हमारे चर्म कारीगरों के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग करने और एक सफल उद्यमी बनने के लिये यह स्वरोजगार का एक बड़ा अवसर है।

उन्होंने कहा कि फुटवियर फैशन का एक अभिन्न अंग बन गया है और जूता बनाने का काम अब एक काम नहीं रह गया है। इस प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से, हम जूता बनाने की गतिविधियों के साथ अधिकतम लोगों को इस कड़ी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि केवल दो माह के समय में, कारीगर सभी प्रकार के जूते बनाने में सक्षम होंगे, जिससे उनकी आय कई गुना बढ़ जाएगी।

◆◆◆◆

"स्थानीय से वैश्विक" विषय पर भविष्य के राजनयिकों के साथ केवीआईसी के अध्यक्ष की चर्चा

16 जुलाई, 2020 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षुओं को सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस, नई दिल्ली में "प्रोमोटिंग ऑफ खादी इन अब्रॉड" (विदेशो में खादी को प्रोत्साहन) पर एक प्रशिक्षण सत्र को संबोधित किया।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने अपने संबोधन के बाद कहा कि यह भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षुओं के साथ एक श्रेष्ठ विचार विनिमय था। मैंने उनसे भविष्य के राजनयिकों के रूप में "स्थानीय से वैश्विक" के राजदूत के रूप में कार्य करने का आग्रह किया। उन्होने कहा कि युवा अधिकारियों को भारत की वृद्धि को पंगु बनाने वाले संदिग्ध विदेशी वित्त पोषित गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ भारत के हितों की रक्षा करना चाहिए।

केवीआईसी ने दौसा में प्रशिक्षित कारीगरों को 100 विद्युत चालित कुम्हारी चाक़ों का वितरण किया

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने राजस्थान में मिट्टी के बर्तनों की पारंपरिक कला को आगे बनाये रखने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है और 100 कुम्हार परिवारों को सशक्त बनाने के लिए राजस्थान के गांव बालाहेड़ी, जिला दौसा में 17 जुलाई 2020 को प्रशिक्षित कारीगरों को 100 विद्युत चालित कुम्हारी चाक़ों का वितरण किया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दौसा की माननीय सांसद, श्रीमती जसुकर उपस्थित थीं।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया।

माननीय सांसद सदस्य दौसा, श्रीमती जसुकर ने केएनएचपीआई, दौसा में हाथकागज और मिट्टी के बर्तनों के स्टाल का दौरा किया ।

केवीआईसी हुआ सख़्त;

प्रधान मंत्री की फोटो इस्तेमाल कर नकली खादी मास्क बेचने वाले के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज

खादी के नाम पर सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर बेचे जा रहे नकली मास्क पर कड़ा संज्ञान लेते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने एफआईआर दर्ज करने के लिए चंडीगढ़ निवासी के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। केवीआईसी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, चंडीगढ़ के पास, सुश्री खुशबू के खिलाफ, "अनधिकृत रूप से" खादी फेस मास्क के रूप में डबिंग कर फेस मास्क बेचने और पैकेट पर माननीय प्रधान मंत्री की तस्वीर का उपयोग करने के लिए शिकायत दर्ज की है।

सुश्री खुशबू द्वारा बेचे जा रहे मास्क पर माननीय प्रधान मंत्री की तस्वीर के अलावा खादी और केंद्र सरकार के "मेक इन इंडिया" के लोगो और "लोकल फॉर वोकल" पहल को भी झूठी धारणा बनाने के लिए उपयोग किया जा रहा है, कि उनका पोर्टल खादी उत्पादों को बेचने हेतु प्राधिकृत है।

यह शिकायत केवीआईसी के राज्य निदेशक, चंडीगढ़ द्वारा दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि यादृच्छिक फेस मास्क धोखे से "खादी फेस मास्क" के रूप में बेचा जा रहा था। इससे न केवल जनमानस में खादी के प्रति गलत व भ्रामक धारणा पैदा हुई, बल्कि वास्तविक ग्राहकों को वास्तविक रूप से खादी मास्क की तलाश है, जो केवीआईसी द्वारा अपने ई-पोर्टल के माध्यम से बेचा जा रहा है।

शिकायत में कहा गया है कि "केवीआईसी के जानकारी में आया है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 15-सी की एक निवासी सुश्री खुशबू ने बिना किसी प्राधिकार के और केवीआईसी की अनुमति के बिना "खादी मास्क" के नाम को मास्क की बिक्री में शामिल किया है। यह भी कहा गया है कि वह पंजीकृत वर्ड मार्क "खादी" और इसके फॉर्मेटिव मार्क का उपयोग करके मास्क बेच रही हैं और इसका व्यापक रूप से विज्ञापन कर रही हैं।

"इसके अलावा, वह विज्ञापन सामग्री में भारत के माननीय प्रधान मंत्री की तस्वीर का भी उपयोग कर रही है, और यह ज्ञात नहीं है कि प्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग पर रोक) अधिनियम, 1950 की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार की अनुमति/ प्राधिकरण की आवश्यकता है जो उनके द्वारा यह

Contd. on ....pg no.16

खादी और ग्रामोद्योग आयोग को रेड क्रॉस सोसाइटी से मिला 1.80 लाख फेस मास्क खरीद का ऑर्डर

आईआरसीएस मास्क, लाल पाइपिंग के साथ भूरे रंग में 100% डबल-ट्विस्टेड दस्तकारी सूती कपड़े से बना होगा। खादी और ग्रमोद्योग आयोग ने विशेष रूप से भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए इन डबल-लेयर्ड कॉटन मास्क को उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए नमूनों के अनुसार डिज़ाइन किया है।

नई दिल्ली: कोरोना महामारी के दौर में खादी से बने फेस मास्क लोगों को पसंद आ रहे हैं। इस मास्क की गुणवत्ता और सस्ती कीमत के कारण खादी और ग्रामोद्योग आयोग को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस) से देशभर में 1.80 लाख मास्क की खरीद का ऑर्डर मिला है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अनुसार, आईआरसीएस मास्क लाल पाइपिंग के साथ भूरे रंग में 100% डबल-ट्विस्टेड दस्तकारी सूती कपड़े से बना होगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने विशेष रूप से भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए इन डबल-लेयर्ड कॉटन मास्क को उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए नमूनों के अनुसार डिज़ाइन किया है। इस मास्क में बाईं ओरआईआरसीएस का लोगो और दाईं ओर खादी इंडिया टैग मुद्रित होगा। अगले महीने तक मास्क की आपूर्ति शुरू हो जाएगी।

जानकारी के अनुसार, इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए 20,000 मीटर से अधिक कपड़े की आवश्यकता होगी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से खरीद ऑर्डर मिलने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि खादी फेस मास्क की भारी मांग "आत्मनिर्भर भारत" की दिशा में एक बड़ा कदम है और इस आदेश से हमारे खादी कारीगरों को अधिक यार्न और कपड़े का उत्पादन करने में मदद मिलेगी। इससे इस कठिन समय में उनकी आय में और इजाफा होगा।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कहा कि अब तक वह 10 लाख से अधिक फेस मास्क बेच चुका है जिसमें डबल लेयर्ड कॉटन मास्क और ट्रिपल लेयर्ड सिल्क मास्क शामिल हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग को फेस मास्क के लिए सबसे बड़ा ऑर्डर जम्मू-कश्मीर सरकार से मिला था, जो कि 7 लाख मास्क का था। लगभग एक करोड़ रुपये से अधिक के सूती कपड़े का लगभग 1 लाख मीटर और विभिन्न रंगों और प्रिंटों के लगभग 2000 मीटर के सिल्क कपड़े का उपयोग इन मास्क को बनाने में किया गया है।

नीति आयोग के सीईओ ने किया गांधी आश्रम सेवापुरी का दौरा

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री अमिताभ कांत ने 17 जुलाई, 2020 को वाराणसी में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा चल रही गतिविधियों का जायजा लेने के लिए गांधी आश्रम, सेवापुरी का दौरा किया। श्री अमिताभ कांत ने सौर चरखे और सौर करघे का निरीक्षण किया जहां कारीगर कताई और बुनाई गतिविधियों को सम्पन्न कर रहे थे। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने कारीगरों को उनके घर पर ही रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के प्रयासों की सराहना की और खादी कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने में सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।

आत्मनिर्भर भारत के लिए केवीआईसी की चंदन और बांस के वृक्षारोपण के पहल की सराहना

नीति आयोग ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग की पहल की सराहना करते हुए राज्यों से चंदन और बांस के वृक्षारोपण के लिए अपील की।

वित्तीय सुदृढ़ता व भारत को "आत्मनिर्भर" बनाने के प्रधानमंत्री के स्वप्न को पूरा करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।

बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र, पंजोखरा में विद्युत चालित चाक वितरित

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कुम्हार सशक्तिकरण मिशन के तहत 30 जुलाई, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौधरी चरण सिंह, बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र, पंजोखरा में प्रशिक्षित कारीगरों को 20 विद्युत चालित चाक वितरित किए।

.....Contd. from pg no. 12

अनुमति ली गई है या नहीं।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा, "हम किसी भी व्यक्ति या निजी कंपनियों को नहीं छोड़ेंगे जो खादी के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं या अनधिकृत रूप से माननीय प्रधान मंत्री की तस्वीर का उपयोग उत्पादों या विज्ञापनों पर कर रहे हैं। यह एक गंभीर उल्लंघन और आपराधिक कृत्य है। यहां तक कि अतीत में हमने ऐसे उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की है।"

यह उल्लेख करना आवश्यक है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपने ब्रांड नाम "खादी इंडिया" के किसी भी दुरुपयोग और इसके ट्रेडमार्क के उल्लंघन में कड़ी कार्रवाई की है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अब तक फैब इंडिया सहित 1000 से अधिक निजी फर्मों को कानूनी नोटिस जारी किया है ताकि खादी के नाम के तहत अपने ब्रांड नाम और उत्पादों की बिक्री न हो सके। केवीआईसी ने नकली खादी के कपड़े की बिक्री के कारण, उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने और खादी कारीगरों की मजदूरी के नुकसान के लिए इन फर्मों से हर्जाना भी मांगा है।

इस साल मई में, दिल्ली स्थित 3 फर्मों को खादी के ब्रांड नाम से नकली पीपीई किट बेचने के लिए केवीआईसी द्वारा कानूनी नोटिस जारी किए गए। हालाँकि, कानूनी नोटिस दिए जाने के बाद, 200 कंपनियों ने केवीआईसी से माफी मांगी है और धोखे से खादी के नाम से किये गये अपने उत्पादों, विज्ञापनों को वापस ले लिया।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने चंडीगढ़ पुलिस से उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का भी अनुरोध किया है जिसमें ब्रांड नाम "खादी" और फॉर्मेटिव मार्क का उपयोग सामान और सभी विज्ञापन, उत्पादों, होर्डिंग्स, प्रचार सामग्री, ब्रोशर, स्टेशनरी, वेबसाइट, सोशल मीडिया वेबसाइटों आदि, को जब्त करना शामिल है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कानूनी विशेषज्ञों की एक टीम बनाई है, जो ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के साथ-साथ बाजारों में कहीं भी खादी के ब्रांड नाम के किसी भी दुरुपयोग पर, और खादी कारीगरों के हितों की रक्षा के लिए सख्त निगरानी रखे है।

गांधी आश्रम में समीक्षा बैठक

15 जुलाई, 2020 को गांधी आश्रम की समीक्षा बैठक, मंडलीय कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मेरठ मे आयोजित की गयी । इस बैठक की अध्यक्षता श्री आर.के. श्रीवास्तव, निदेशक, मंडलीय कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मेरठ ने की। बैठक के दौरान सभी ने सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशो का पालन किया ।

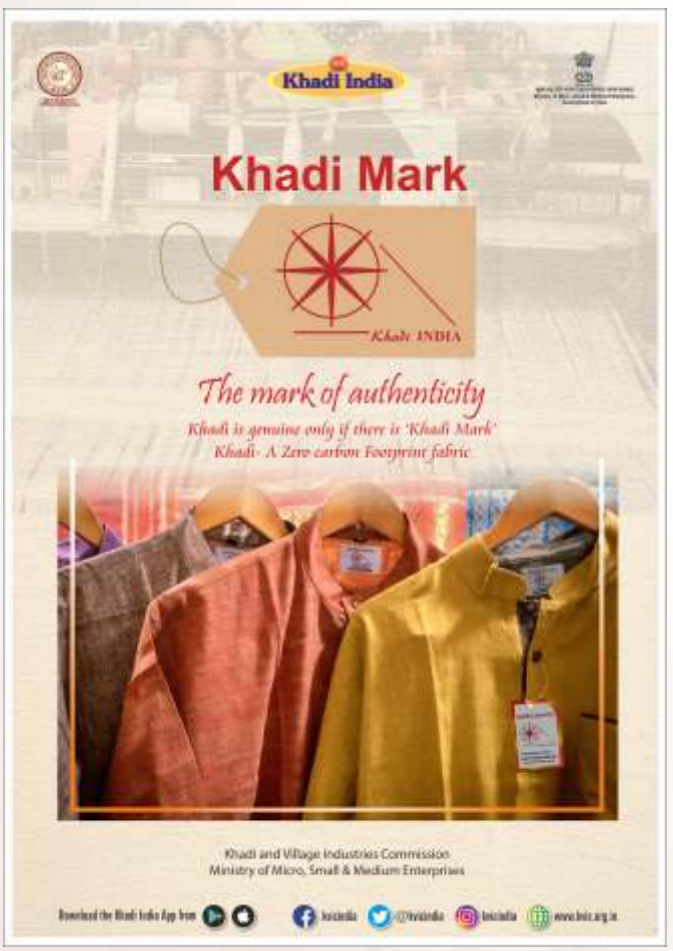

श्री बी.एल मीणा, निदेशक, राज्य कार्यालय, केवीआईसी, जयपुर ने केएनएचपीआई जयपुर में मोरिंगा के पौधों का रोपण किया ।

कोरोना संकट और स्व-रोज़गार के अवसर

कोरोना संकट काल में दुनिया में जो हालात बने हैं, उससे आने वाले दिनों में उत्पन्न होने वाली परेशानियों को समझना मुश्किल नहीं है। भारत जैसे देश के लिए तो स्थिति और भी विकट है। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर कोरोना की वजह से स्थिति बिगड़ी तो देश को और भी बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना होगा। कोरोना वायरस महामारी के प्रसार पर अंकुश के लिये लागू लॉकडाउन के तीसरे चरण के समाप्त होने से पांच दिन पहले राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट के इस दौर में 'लोकल' ने ही हमें बचाया है। स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों ने ही आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है और हमें इसे ही अपने आत्मनिर्भर बनने का मंत्र बनाना चाहिये। भारत में स्वदेशी आन्दोलन का जोर 1905 में जोर पकड़ा था। इसका मुख्य उद्देश्य अपने देश की वस्तु को अपनाना था। इसके पीछे की सोच यह थी कि भारत की तरक्की भारतीयों और भारतीय द्वारा बनायी गई वस्तुओं से ही सम्भव है।

प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ना सिर्फ लोकल प्रोडक्ट के इस्तेमाल की बात कही है बल्कि इसे प्रचारित कर ग्लोबल बनाने का भी आग्रह किया है। उन्होने लोकल, वोकल और ग्लोबल (Vocal for Local) की बात यूं ही नहीं कही है। इसके पीछे एक बड़ी सोच है। कोरोना संकट ने हमें लोकल सप्लाई चेन का महत्व भी समझा दिया है। हमें इसी लोकल चेन ने बचाया। जो आज ग्लोबल ब्रांड हैं, वे भी कभी लोकल थे। अब ये प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल हो गए हैं। इसलिए आज हर भारतवासी को लोकल के लिए वोकल बनना होगा। इसके लिए हमें न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट खरीदना है बल्कि उनका गर्व से प्रचार करना है, हमें लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देना है और लोकल से ग्लोबल मंत्र को अपनाकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए संकल्प लेना है।

कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया है। 'मेक इन इंडिया' को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले आत्मनिर्भरता, आत्मबल को अपनाना होगा और यही 'समय की मांग है कि भारत हर प्रतिस्पर्धा में जीते, सरकार द्वारा इसके लिए अनेक प्रावधान किये गये हैं, जिससे क्षमता बढ़ेगी, गुणवत्ता बेहतर होगी। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए, एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की, इस पैकेज में Land, Labour, Liquidity और Laws, सभी पर बल दिया गया है। यह आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु-मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए है, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन हैं और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का मजबूत आधार हैं। स्थानीय उत्पादों के मामले में खादी और ग्रामीण उद्योग का उदाहरण एक मिसाल है, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री ने लोगों से इन उत्पादों को खरीदने का आग्रह किया, तो इन उत्पादों की बिक्री रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई और इसका काफी अच्छा परिणाम हमें देखने को मिला।

पिछले पांच वर्षों में, भारत में 'ब्रांड खादी' की स्वीकार्यता व्यापक रूप से देखने को मिली है। जबकि खादी का उत्पादन पिछले पांच वर्षों में दोगुने से भी ज्यादा हो चुका है, यानी 2015-16 के बाद से; इसी अवधि के दौरान खादी की बिक्री में लगभग तीन गुनी बढ़ोत्तरी देखी गई है।

इसी प्रकार, ग्रामोद्योग क्षेत्र के उत्पादन और बिक्री में भी पिछले पांच वर्षों में लगभग 100% की अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी देखी गई है। वर्ष 2019-20 में, खादी एवं ग्रामोद्योग का कुल कारोबार 88,887 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

"कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई बड़ी है, इसके लिए हर देशवासी को संकल्प लेकर इस आपदा को अवसर में बदलना होगा और यही समय आत्मनिर्भर बनाने का और भारत को अपने पैरों पर खड़ा होना का। हार मानने वालों को मौके नहीं मिलते। "लोकल के लिए वोकल होने का समय आ गया है।

इसके लिए देश के विकास में युवा आगे आएं और आत्मनिर्भरता के पाठ की शुरुआत अपने परिवार से करें, छोटे दुकानदारों से सामान खरीदें। आज स्वदेशी सामानों का उपयोग बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिये हम सबको सोचना होगा, हम सबको मिलकर आगे आना होगा, तभी भारत विश्व पटल पर एक बड़ा निर्यातक बन सकेगा।"

जब कोविड-19 लॉकडाउन के कारण देश की अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगा है, ऐसे समय में देश के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने व्यापक उद्देश्यों के साथ देश भर में अपने स्वरोजगार उन्मुख योजनाओं के माध्यम से एक विस्तृत अभियान चलाया है। और, यह बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि देश में जहाँ कोविड- 19 संकट के कारण व्यवस्थाएं सुस्त हुई हैं, वहीं खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपने कुशल अध्यक्ष के नेतृत्व में इसे एक अवसर के रूप में एक विस्तृत कार्य योजना के साथ पूरे देश में एक व्यापक स्व रोजगार सृजन अभियान चलाया है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के "वोकल फ़ॉर लोकल" बनने और बाद में इसे "वैश्विक" बनाने के लिए जोर दिया है। स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री की अपील के एक दिन बाद, केवीआईसी ने प्रमुख कार्यक्रम पीएमईजीपी के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कई दिशानिर्देशों को जारी किया।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा क्रियान्वित प्रमुख कार्यक्रम "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम" काफी तेज़ी से आगे बढ़ा है। मौज़ूदा वित्तीय वर्ष के पहले पांच महीनों अर्थात 1 अप्रैल, 2020 से 18 अगस्त, 2020 के दौरान परियोजनाओं की स्वीकृति में 44 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 71,556 परियोजनाओं की तुलना में 1.03 लाख परियोजनाओं को मंजूरी दी और वित्त पोषण बैंक को अग्रेषित किया है, इस प्रकार तुलनात्मक रूप से परियोजनाओं के क्रियान्वयन में 44% की छलांग दर्ज हुई है।

यह वर्ष पीएमईजीपी परियोजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन में अत्याधिक महत्व रखता है वह भी तब जब कि पूरे देश में इन पांच महीनों के अधिकांश समय लॉकडाऊन लागू रहा। परियोजनाओं की संख्या अधिक होना, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देकर लोगों के लिए स्वरोजगार और स्थायी आजीविका बनाने के सरकार के संकल्प का प्रतीक हैं। पीएमईजीपी परियोजनाओं के अनुमोदन में भारी वृद्धि माननीय प्रधानमंत्री के "मिनिमम गवर्मेन्ट मैग्ज़िमम गिवेर्नेन्स' के आह्वान का परिणाम है, जो जिला कलेक्टरों की भूमिका को बंद करने से परियोजनाओं का तेजी से कार्यान्वयन करना सुनिश्चित हुआ है। हालाँकि, बैंकों को भी धनराशि स्वीकृत करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक संख्या में आवेदकों को लाभ मिल सके।

स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि देश में मौजूदा कोविड -19 स्थिति के कारण बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम एक एन 95 मास्क, वेंटिलेटर या इसके सामान के निर्माण से संबंधि इकाई, चिकित्सा कर्मचारियों के लिए पीपीई किट, सैनिटाइज़र, थर्मल स्कैनर तथा अगरबत्ती और साबुन इकाई की स्थापना की जाए।

कोरोना महामारी के दौर में खादी से बने फेस मास्क लोगों को पसंद आ रहे हैं। इस मास्क की गुणवत्ता और सस्ती कीमत के कारण खादी और ग्रामोद्योग आयोग को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से देशभर में 1.80 लाख मास्क की खरीद का ऑर्डर मिला है। अब तक आयोग, 10 लाख से अधिक फेस मास्क बेच चुका है जिसमें डबल लेयर्ड कॉटन मास्क और ट्रिपल लेयर्ड सिल्क मास्क शामिल हैं। आयोग को फेस मास्क के लिए सबसे बड़ा ऑर्डर जम्मू-कश्मीर सरकार से मिला था, जो कि 7 लाख मास्क का था। लगभग एक करोड़ रुपये से अधिक के सूती कपड़े का लगभग 1 लाख मीटर और विभिन्न रंगों और प्रिंटों के लगभग 2000 मीटर के सिल्क कपड़े का उपयोग इन मास्क को बनाने में किया गया है। आयोग को राष्ट्रपति भवन, प्रधान मंत्री कार्यालय, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, जम्मू-कश्मीर सरकार से आपूर्ति आदेश के साथ ही आम जनता से ईमेल के माध्यम से

आदेश प्राप्त हुए हैं । बिक्री के अलावा, देश भर में खादी संस्थाओं द्वारा 7.5 लाख से अधिक खादी मास्क हर जिले में जिला अधिकारियों को मुफ्त में वितरित किए गए हैं।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने दुबई, अमेरिका, मॉरीशस और कई यूरोपीय और मध्य पूर्व देशों जैसे खादी फेस मास्क की आपूर्ति करने की योजना बनाई है जहां पिछले कुछ वर्षों में खादी की लोकप्रियता काफी बढ़ी है । आयोग ने भारतीय दूतावासों के माध्यम से इन देशों में खादी मास्क बेचने की योजना बनाई है।

भारत के सीमान्त कुम्हार समुदाय को "आत्मनिर्भर" बनने की दिशा के साथ उन्हें सशक्त और रोज़गार अवसर प्रदान करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपने कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम के माध्यम से कुम्हारी उद्योग से ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए पूरे देश में एक अभियान चला रखा है। देश भर में अब तक 17,000 से अधिक विद्युत चालित कुम्हारी चाक वितरित किए जा चुके हैं, जिससे कुम्हार समुदाय के लगभग 70,000 लोग लाभान्वित हुए हैं। इसने कुम्हारों के जीवन को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है । विद्युत चालित कुम्हारी चाकों के साथ, मिट्टी की वस्तुओं का उत्पादन कई गुना बढ़ गया है । वर्तमान में, देश भर में हर दिन लगभग 2 करोड़ कुल्हड़ बनाए जाते हैं। कुम्हार इन कुल्हड़ को 400 रेलवे स्टेशनों पर सफलतापूर्वक बेच रहे हैं जो उनके लिए एक आदर्श विपणन मंच है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने वाराणसी में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कुम्हार समुदायों को मिट्टी के दीयों, देवी/देवताओं की मूर्तियों और मिट्टी के अन्य बर्तनों को बनाने का प्रशिक्षण दे रहा है। केवीआईसी ने हाल ही में वाराणसी के चार गांवों - इटहराडीह, अहरौराडीह, अर्जुनपुर और चक सहजंगीगंज के मिट्टी के बर्तन बनाने वाले समुदायों से जुड़े 80 परिवारों को विद्युत चालित कुम्हारी चाक वितरित किए हैं। इनमें से हरेक गांव में लगभग 150 से 200 कुछ ऐसे परिवार रहते हैं जो कई पीढ़ियों से मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं । हालांकि, हाथ से संचालित किए जाने वाले चाकों की पुरानी तकनीकों, हाथों-औजारों से मिट्टी तैयार करने और बाजार/मांग की कमी के कारण ये लोग अपना पुश्तैनी काम छोड़ कर दूसरे विकल्प तलाशने के लिए मजबूर थे।

देश का अगरबत्ती उद्योग भी आत्मनिर्भर बनने के लिए पूरी तरह तैयार है । हाल ही में सरकार ने बंबू स्टिक्स पर इंपोर्ट ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 25% कर दी है। दरअसल, भारत में अगरबत्ती की स्टिक्स चाइना और वियतनाम से आती हैं। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से मैन्युफैक्चरर वहां से माल मंगाने की बजाय घरेलू माल की खपत ज्यादा करेंगे । ऐसा करने से देसी सामान की खपत होगी और घरेलू लोगों को ज्यादा रोजगार मिल सकेगा । खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अगले 10 महीने में अगरबत्ती उद्योग में कम से कम एक लाख रोजगार पैदा किए जाएंगे । अगरबत्ती उद्योग में देश के बहुत सारे गांव लगे हुए हैं और जल्द ही इस उद्योग के व्यापक रोज़गार क्षेत्र से देश के युवा बड़ी संख्या में जुड़ेंगें। इसका पूरा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री और हमारे एमएसएमई मंत्री को जाता है, जिनकी वजह से अगरबत्ती उद्योग आत्मनिर्भर बनेगा।

स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना 'आत्मनिर्भरता' के आह्वान के क्रियान्वयन का ही एक हिस्सा है। कोविड महामारी के कारण लोगों के रोज़गार जा रहे हैं, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इसे एक अवसर के रुप में लिया है, अब युवाओं को अन्य राज्यों में नौकरियों की तलाश में अपने घरों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें अपने परिवार को दूसरे शहरों में नौकरी खोजने के लिए छोड़ कर नही जाना होगा। क्योंकि आयोग के हनी मिशन कार्यक्रम से जुड़कर वह बेहतर आजीविका बनाने में सक्षम हो सकेंगे। विशेष रूप से, केवीआईसी द्वारा तीन साल पहले शुरू किए गए हनी मिशन का उद्देश्य किसानों, आदिवासियों, महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को मधुमक्खी पालन से स्थानीय स्तर पर रोज़गार के अवसरों के साथ साथ भारत के शहद उत्पादन में वृद्धि करना है। अब तक खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में 1.35 लाख मधुमक्खी बक्से वितरित किए हैं। इससे लगभग 8500 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन हुआ और देश भर में 13,500 लोग लाभान्वित हुए हैं।

"मधुमक्खी पालन से न केवल भारत में शहद उत्पादन बढ़ेगा बल्कि इससे मधुमक्खी पालकों की आय भी बढ़ेगी। इसके अलावा, मधुमक्खी के मोम, पराग, प्रोपोलिस, रायल जेली और मधुमक्खी के जहर जैसे उत्पाद भी बाजार में बेचे जा सकते हैं, अतः स्थानीय लोगों के लिए यह एक लाभदायक उद्यमी कार्य है।

भारत गावों का देश है, गाँधी जी ने कहा था की गांव का सुधार होगा तो देश सुधरेगा। अब सचमुच गांव उत्कृष्ट और एक आदर्श गांव बन रहे हैं। ग्रामीण युवकों को अब शहरों की ओर भागने या पलायन करने की जरूरत नहीं, गांवों में ही उद्योग लगाने के लिए लोन की सुविधा है, और तो और तकनीक भी मिल रही है। खादी ग्रामोद्योग विकास योजना- रोजगार युक्त गाँव योजना को खासतौर पर सभी निम्न वर्ग के लोगों के लिए शुरू किया गया है । इस योजना से हजारों नए कारीगरों को रोजगार के अवसर दिए जायेंगे । इस योजना में प्रत्येक गांव से लगभग 250 कारीगरों को प्रत्यक्ष रोजगार दिये जायेंगे तथा कारीगरों को चरखे, करघे आदि दिए जायेंगे। खादी ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 2019-20 में मौजूद सब्सिडी के नेतृत्व वाले मॉडल को सम्पूर्ण रूप से बदल दिया जाएगा। इसके साथ ही खादी ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत एक नए आयाम "रोजगार युक्त गांव" को जोड़ा गया है। जिसके चलते खादी क्षेत्र में उपक्रम आधारित परिचालन शुरू भी किया जा सके। खादी ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत वित्त वर्ष 2019-20 में हजारों नए कारीगरों के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर दिए जाएंगे।

रोज़गार युक्त गाँव (RYG) का उद्देश्य - तीन हितधारकों- KRDP केआरडीपी-सहायता प्राप्त खादी संस्थान, कारीगरों और व्यापार साझेदार के बीच साझेदारी के माध्यम से 'सब्सिडी-नेतृत्व वाले मॉडल' के स्थान पर 'एंटरप्राइज-लीडेड बिजनेस मॉडल' की शुरुआत करना है। ग्राम उद्योग कार्यक्षेत्रों के तहत, उत्पाद नवाचार, डिजाइन विकास और उत्पाद विविधीकरण के माध्यम से कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण (शहद, पामगुर आदि), हस्तनिर्मित कागज और चमड़ा, मिट्टी के बर्तनों और सौंदर्य प्रसाधन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इस योजना के तहत खादी कारीगरों को 10,000 चरखे, 2000 करघे प्रदान किये जाएंगे । रोजगार युक्त गाँव योजना प्रति गांव 250 कारीगरों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगा। इस योजना के तहत प्रति गाँव में कुल पूँजी निवेश 72 लाख रुपये सब्सिडी के रूप में और 1.64 करोड़ रुपये व्यापार भागीदार से कार्यशील पूंजी के रूप में अनुमानित है । इस पहल के लिए, उन्नत कौशल विकास कार्यक्रम सीजीसीआरआई, सीएफटीआरआई, सीबीआरटी आई, केएनएचपीआई, आईपीआरआईटीआई आदि जैसे उत्कृष्टता केन्द्रों के मौजूदा केंद्रों के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे । इस आरवाईजी योजना के तहत वित्त वर्ष 2019-20 में हजारों नए कारीगरों के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। सभी खादी संस्थाओं को 30% अनुदान मिलेगा और ये संस्थाएं दक्षता, संसाधनों के इष्टतम उपयोग, अपशिष्ट की कमी और प्रभावी प्रबंधकीय प्रथाओं के लिए अतिरिक्त 30% प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी।

केवीआईसी ने हाल ही में शुरुआती तौर पर सीएपीएफ कैंटीन को शहद, अचार, खाद्य तेल, अगरबत्ती, पापड़, आंवला कैंडी और सूती खादी से बने तौलिए आदि जैसे उत्पादों की आपूर्ति की है। केवीआईसी और आईटीबीपी ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, इस आपूर्ति श्रृंखला में 63 नए उत्पादों को जोड़ने के लिए सूची तैयार की जा रही है। इसके साथ ही आईटीबीपी ने 1200 क्विंटल उच्च गुणवत्तायुक्त कच्ची घानी सरसों के तेल की आपूर्ति के लिए एक आर्डर दिया है, जिसकी आपूर्ति केवीआईसी द्वारा अपनी पीएमईजीपी इकाइयों के माध्यम से एक महीने के भीतर की जाएगी।

निसंदेह, आने वाले समय में देश के समवेशी विकास में गांधीवादी ग्रामीण पुर्निनिर्माण संरचना की अवधारणा पुनः स्थापित होगी और आत्मनिर्भर भारत बनाने में खादी और ग्रामोद्योग आधारित कार्यक्रमों की एक व्यापक भूमिका होगी।

- सुबोध कुमार

प्रेस कवरेज

'कुम्हार शक्तिकरण योजना' कुम्हार समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण कदम : शाह

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा केवीआईसी की 'कुम्हार शक्तिकरण योजना' के तहत अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में 100 विद्युत चाक का वितरण किया

प्रधानमंत्री मोदी का इलेक्ट्रिक चाक का वितरण गुजरात के लोगों के लिए उपहार : शाह

खादी ग्रामोद्योग ने बदली आतंक पीड़ित लोगों की जिंदगी

केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान : मीना

सीमा सन्देश

अब कुम्हार चलाएंगे इलैक्ट्रिक चाक

खादी ग्रामोद्योग ने कुम्हारों को दिया प्रशिक्षण

200 और कुम्हारों को दिया जाएगा प्रशिक्षण

प्रेस कवरेज

STAR OF MYSORE Tuesday 28th July 2020

STAR OF MYSORE

Editor: M. GOVINDE GOWDA, M.A.

Appointed as Chief Advisor to Khadi and Village Industries Commission

No power supply on July 29 and July 30

NEWS SPARKLER — World's first man-made ... cuttable mat...

कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान उत्कृष्टता के लिए केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगाः बी एल मीना

किशनगंज। बद्री लाल मीना खादी ग्राम और उद्योग सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ...कार जयपुर द्वारा कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ ...संस्थान सांगानेर जयपुर के निदेशक का ... कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत ...कि यह भारत सरकार में एकमात्र ... संस्थान है तथा इस संस्थान को ... के लिए केंद्र सेंट्रल और एक्सलाइंस ...में विकसित किया जाएगा। संस्थान के ... का कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत ...थम उद्बोधन में बी एल मीना ने बताया ...ान अच्छी तरह से सभी बुनियादी और ...विधाओं और मशीनरी के साथ सुजीत है। अपने कागज प्रशिक्षण रासायनिक और जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला के अलावा पायलट प्रदर्शन केंद्र के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। संस्थान द्वारा हाथ कागज में अनेक तरह के प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। हाल ही में कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान द्वारा नारियल फूलों इत्यादि से निर्मित हवन सामग्री तथा गाय के गोबर और लुगदी मिश्रित हाथ कागज का उत्पादन किया जा रहा है। संस्थान द्वारा निर्मित फूलों और नारियल के छिलकों से शुभ हवन सामग्री की गुणवत्ता बाजार में बिक रही हैं अन्य हवन सामग्री से ना केवल बेहतर बल्कि इसकी कीमत भी उनके मुकाबले कम है प्रयोगशाला के प्रशिक्षण में भी यह सिद्ध हुआ कि हमारे शुभ हवन सामग्री का ग्रास कैलोरिक वैल्यू भी बाजार में उपलब्ध अन्य हवन सामग्रीओं के मुकाबले अधिक है। मीणा ने बताया कि संस्थान से पुष्प और सुगंधी का उपयोग करते हुए अगरबत्ती का प्रशिक्षण दिया जाएगा और अगरबत्ती का भी उत्पादन किया जाएगा इस संस्थान ने रद्दि कपड़ों के साथ प्लास्टिक मिलाकर पेपर बैग ना केवल हमें रक्तबीज रूपी प्लास्टिक जैसे दानव से आंशिक रूप से मुक्ति दिलाएगा बल्कि इससे हमारी नालियां भी अवरुद्ध नहीं होंगी और पर्यावरण भी शुद्ध होगा।

खादी और हाथ कागज बनाना आय के अच्छे स्रोत : बद्रीलाल

मीना ने संभाला कागज संस्थान का अतिरिक्त चार्ज

रायसर, 1 जुलाई (अशोक) : खादी और ग्रामोद्योग के राज्य निदेशक बद्रीलाल मीना ने कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान सांगानेर के निदेशक पद का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया है।

पदभार लेते अतिरिक्त निदेशक बद्रीलाल मीना।

इस दौरान मीना ने औपचारिक बातचीत में बताया कि कागज संस्थान अच्छी तरह से सभी बुनियादी व उन्नत मशीनों की सुविधा के साथ सुसज्जित है। संस्थान अपने कागज प्रशिक्षण, रासायनिक व जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला के अलावा पायलट सह प्रदर्शन केन्द्र के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। कागज संस्थान में अनेक तरह के प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान द्वारा नारियल व फूलों इत्यादि से निर्मित हवन-सामग्री तथा गाय के गोबर व लुगदी मिश्रित हाथ कागज का उत्पादन भी किया जा रहा है। संस्थान द्वारा तैयार हवन सामग्री बाजार में बिकने वाली गुणवत्ताविहिन सामग्री से न केवल उच्च कोटी बल्कि कीमत के मुकाबले भी कम है।

मीना ने बताया कि पुष्प व सुगंधी का उपयोग कर के आने वाले दिनों में अगरबत्ती का भी प्रशिक्षण देंगे। जिससे रोजगार के साधन बढ़ेंगे। संस्थान द्वारा रद्दी कपड़ों के साथ प्लास्टिक मिलते हुए पेपर बैग का भी उत्पादन किया जा रहा है। इस तकनीक से पॉलिथीन कचरे से काफी निजात मिलेगी।

पंजाब केसरी ई-पेपर Thu,02 July 2020 Edition: shri ganga nagar, Page no: 4

कुमारप्पा राष्ट्रीय संस्थान उत्कृष्टता का केंद्र बनेगा : मीना

HEADLINES e NEWS

Circle: Local News & Videos Get it on Google Playstore

कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान उत्कृष्टता के लिए केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा,, बीएल मीना बद्रीलाल मीणा खादी ग्राम उद्योग आयोग सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार जयपुर द्वारा कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान सांगानेर जयपुर के निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत बताया कि यह भारत सरकार में एक मात्र सरकारी संस्थान है तथा इस संस्थान को उत्कृष्टता के लिए केंद्र सेंट्रल और एक्सलाइंस के रूप में विकसित किया जाएगा...

सोशल मीडिया अभियान

इंस्टाग्राम ग्रिड

• Special Day posts •

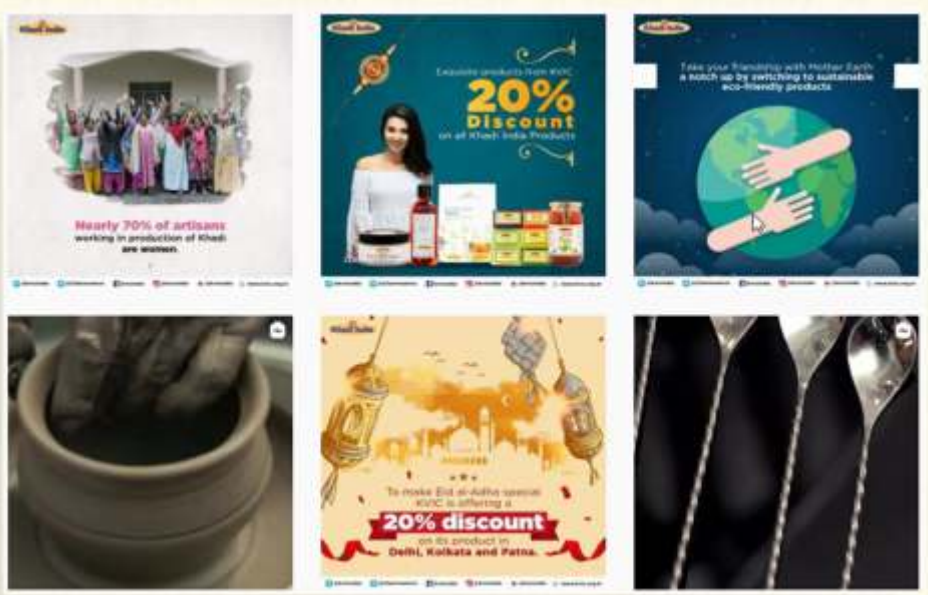

सोशल मीडिया अभियान

पोस्ट श्रंखला

Khadi India

शहद की माया, निरोग रहे काया

शहद एक पूर्ण संतुलित आहार है जो सूक्ष्म पोषक तत्वों, एंटिऑक्सिडेंट्स, स्वादिष्ट और रोगों से लड़ने वाले गुणों से भरा हुआ है।

अपने दैनिक आहार में शहद के दो चम्मच शामिल करें। प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहें।

शुद्ध शहद के लिए कृपया अपने नजदीकी खादी इंडिया आउटलेट्स से संपर्क करें।

जनहित में जारी
खादी और ग्रामोद्योग आयोग
वनाधारित उद्योग
ग्रामोदय, 3, इर्ला रोड, विले पार्ले (प.), मुंबई-400 056
जानकारी के लिए संपर्क करें
ई-मेल: fbi.kvic@gov.in